उम्मीदों भरा महत्त्वाकांक्षी बजट

मुख्यमंत्री महोदय ने अपने चौथा बजट पेश करते हुए घोषणाओं का अम्बार लगा दिया। तीन घंटे लम्बे भाषण में मुख्यमंत्री महोदय ने शायद ही कोई वर्ग होगा जिसके लिये इस बजट में घोषणा नहीं की हो। बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिये महानरेगा में 100 के बदले 125 दिन का काम और शहरों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा, स्कूली छात्रों के लिये 3 माह का ब्रीज कोर्स, 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों के लिये 50 यूनिट मुफ़्त बिजली तथा 2–3 रूपए प्रति युनिट बिजली व 10 लाख नये परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ना आदि घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बजट में सबसे बड़ी घोषणा है, सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली। बजट घोषणा के मुताबिक 2004 से बहाल हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पुराने तर्ज पर ही बाहाल किया जायेगा। जाहिर है ये सभी घोषणाएं ऐसी हैं जो कोरोना संकट से जुझ रहे नागरिकों के लिये काफी सहायक साबित हो सकती हैं। लेकिन इन घोषणाओं को लागू करने के लिये बजटीय आवंटन के साथ ही चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत होगी। बढ़े हुए बजट आवंटन के लिये सरकार के राजस्व आय में सुधार होना भी आवश्यक है, जो काफी हद तक राज्य की अर्थव्यवस्था में हुए सुधार पर निर्भर है।

बजट में वर्ष 2022–23 में 2.15 लाख करोड़ रूपए का राजस्व आय अनूमानित है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 16.6 प्रतिशत अधिक है। क्या राज्य सरकार के राजस्व आय में इतनी वृद्धि हो पायेगी। इस वर्ष (2021–22) में के संशोधित बजट में 1.84 लाख करोड़ रूपए के राजस्व आय होने वाला है जो बजट अनुमान से लगभग 5 हज़ार करोड़ रूपए अधिक है लेकिन अगर सीएजी द्वारा दिसंबर 2021 तक के आंकड़े देखें जाएं तो इस वर्ष के 9 महिनों में कुल अनुमानित राजस्व आय का 63 प्रतिशत ही प्राप्त हो सका है।

लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने आगामी वर्ष के राजस्व आय में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। संभवतः इसका कारण है 2021–22 में इस तेज़ आर्थिक वृद्धि। राज्य की आर्थिक समिक्षा 2021–22 के अनुसार पिछले वर्ष के नाकारात्मक आर्थिक वृद्धि के मुक़ाबले इस वर्ष (2021–22) में 11.1 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि होने का अनुमान है। इसके साथ ही राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी लगभग छः हज़ार रूपए बढ़ी है।

जाहिर है सरकार को आशा है कि राज्य में आर्थिक वृद्धि आने वाले वर्ष भी जारी रहेगी और सरकार की आय भी बढ़ेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी को भी ध्यान में रखते हुए शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की है।

मनरेगा में 125 दिन काम के अलावा सरकार ने भर्तीयों में तेजी का आश्वासन, 'घर से काम' की योजना, महिलाओं को समार्ट फोन देने आदि की घोषणाएं भी महत्त्वपूण हैं। अगर सामाजिक क्षेत्रों के बजट आवंटन की बात करे तो सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण एवं पोषण, अ.जा. जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण तथा ग्रामीण विकास के बजट में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी की है।

बजट में महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं हुई है, जैसे घर से काम, मातृत्व लाभ योजना में दूसरे प्रसव पर लाभ को सभी जिलों में लागू करना आदि। अगर हम जेण्डर बजट का आकार भी 35730 करोड़ रूपये से बढ़कर 69851 करोड़ रूपए (लगभग दो गूना) हो गया है। लेकिन इसमे ज्यादातर बढ़ोतरी 'ब' श्रेणी में हुई है जिसमें वो योजनाएं होती हैं, जिनमें 33 से 99 प्रतिशत तक महिला लाभार्थी होती हैं। जबकि 'अ' श्रेणी जिसमें वो योजनाएं होती हैं, जिनमें 100 प्रतिशत महिला लाभार्थी होती है, का बजट भी लगभग डेढ़ गुना बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में पहली बार कृषि बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र में 11 मिशन की घोषणा की, जिसमें खेतीहर मजदूरों पर मिशन तथा मोटे अनाज पर मिशन भी शामिल हैं। जाहिर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथा स्वागत योग्य घोषणाएं हैं। फसल

कृषिकर्म का बजट 3768 करोड़ रूपए से बढ़कर 6010 करोड़ रूपए हो गया है। सहकारिता के बजट में कमी आई है जो पिछले 2–3 वर्षों में कर्ज माफी के कारण काफी बढ़ गया था। सिंचाई के बजट में भी 30 इस वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अच्छी बात यह है कि लघु सिंचाई का बजट तथा कुल सिंचाई बजट में इसका हिस्सा भी बढ़ा है। सरकार द्वारा दिये गये कृषि बजट के विवरण (खण्ड–4द) में कृषि क्षेत्र का बजट से आवंटन 46,145 करोड़ रूपए है। इसमें कृषि एवं संबद्ध सेवाओं और सिंचाई के अलावा अन्य विभागों द्वारा चलाये जा रहे कृषि से संबंधित योजनाओं को भी शामिल किया गया है।

जाहिर है बजट का आकार भी काफी बढ़ा है। राज्य बजट का आकार भी इस साल के बजट के मुकाबले 38 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। सरकार ने बजट के आकार में यह बढ़ोत्तरी राजस्व आय में अनुमानित बढ़ोत्तरी के साथ बढ़े कर्ज़ के आधार पर भी किया है।

यह सारी क़वायद इस अनुमान पर आधारित है कि 2022–23 में पुनः आर्थिक वृद्धि की दर 11 प्रतिशत की रहेगी। ज़ाहिर है यह एक महत्त्वाकांक्षी बजट है जिसके सफल होने की उम्मीद सबको रहेगी।